

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज

भोपाल, शनिवार 25 से 31 जुलाई 2026

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 14

अंक-102

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5 /-

पीएम मोदी ने जींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया

हरित परिवहन में नया युग, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा रेलवे नेटवर्क

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का उद्घाटन कर दिया। यह उपलब्धि भारत को हरित परिवहन के क्षेत्र में विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित करती है। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाली है और पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प साबित होगी। यह ट्रेन भारतीय रेलवे की नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत और नेट-जीरो लक्ष्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। हाइड्रोजन ट्रेन की सफलता से रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी आएगी।

इस विकास से हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों को फायदा होने की संभावना है। विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में पहले से सक्रिय हैं और आगे और मजबूत स्थिति बना सकती हैं। हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।

यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार सृजन में भी योगदान देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन ट्रेनों का विस्तार पूरे देश में होने पर ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी।

सरकार की हरित गतिशीलता नीति के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। यह उद्घाटन भारत को वैश्विक हरित परिवहन हब बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।



परास डिफेंस की सहयोगी कंपनी मध्य प्रदेश में लगाएगी ₹6,200 करोड़ का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट

राज्य में टेक क्रांति, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती; हजारों रोजगार और आर्थिक विकास का नया दौर

भोपाल: परास डिफेंस की सहयोगी कंपनी ने मध्य प्रदेश में ₹6,200 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। यह परियोजना राज्य को देश के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह प्लांट उन्नत चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग पर काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर की जरूरतों को पूरा करेगा। परियोजना से राज्य में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, खासकर इंजीनियरिंग और टेक्निकल युवाओं के लिए।

यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। स्थानीय उद्योगों को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और युवाओं को उच्च वेतन वाले रोजगार उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश अब सेमीकंडक्टर और हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग का केंद्र बनने जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का विकास होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सक्रिय पहल से राज्य में निवेश का सिलसिला तेज हुआ है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी।



एक खराब सेब पूरे टोकरे को खराब कर देता है

निवेश में भी, एक गलत फैसला आपके पूरे पोर्टफोलियो पर असर डाल सकता है।

✓ मजबूत पोर्टफोलियो

✗ समस्या यहीं से शुरू हो सकती है।

⚠ समीक्षा करें, सही दिशा चुनें।

समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा से कमज़ोर निवेशों का पता चल सकता है, जो बाकी निवेशों पर असर डालने से पहले बदले जा सकते हैं।



आज ही अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें! अधिक जानकारी के लिए जुड़ें।

प्रमुखता से निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

☎ (+91)7389912025

✉ visionadvisorymkt@gmail.com

Vision Invest Tech Pvt. Ltd.

India Stands Firm on Fair Trade Rules at WTO Review in Geneva

Reaffirms Strong Commitment to Multilateral Trading System Amid Global Challenges

Geneva: India has strongly reaffirmed its commitment to a rules-based multilateral trading system during the latest Trade Policy Review at the World Trade Organization (WTO) in Geneva. The country emphasised the importance of transparency, predictability, and inclusivity in global trade governance.

In its detailed presentation, India highlighted its ongoing economic reforms, focus on export diversification, and efforts to integrate more deeply into global value chains. The review process provided an opportunity for member countries to discuss India's trade policies and their impact on the global trading system.

India reiterated its support for WTO reforms that address the concerns of developing nations while maintaining the core principles of non-discrimination and special and differential treatment. The delegation stressed the need for resolving pending issues such as fisheries subsidies and public stockholding for food security.

This participation underscores India's proactive role in shaping the future of global trade. As one of the fastest-growing major economies, India's stance at the WTO carries significant weight in ongoing negotiations.

The review comes at a time when the multilateral trading system faces multiple challenges, including rising protectionism and supply chain disruptions. India's firm commitment sends a positive signal towards preserving and strengthening the rules-based order that has benefited developing economies over the decades.



BHEL का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार: ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी का बड़ा कदम, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता को मजबूती

नई दिल्ली: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने अपने प्लांट्स के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। कंपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने और हरित ऊर्जा उत्पादों पर फोकस कर रही है।

BHEL ने अपनी फैक्टरियों में नई मशीनरी और डिजिटल सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इससे कंपनी की दक्षता बढ़ेगी और लागत कम होगी। कंपनी का लक्ष्य सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स, टरबाइन्स और रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना है।

यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। BHEL पहले से ही कई बड़े पावर प्रोजेक्ट्स में योगदान दे रही है। आधुनिकीकरण से कंपनी ग्लोबल कॉम्पिटिशन में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी।

इस विस्तार से कई क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा। सप्लाय चेन को मजबूती मिलेगी और छोटे उद्योग लाभान्वित होंगे।

BHEL का यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को नई गति प्रदान करेगा। कंपनी हरित हाइड्रोजन और सोलर प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है।



Trump Administration Rolls Out Aggressive Generic Drugs Tariff Plan: Zero for Two Years, then 100%, Followed by 200%

Indian Pharma Exporters Brace for Impact as US Policy Targets Low-Cost Imports

Geneva: The Trump Administration has unveiled a sweeping tariff plan on generic drugs, offering a two-year grace period before imposing 100% tariffs, followed by 200% in subsequent years. The move aims to boost domestic manufacturing and reduce reliance on foreign supplies, particularly from India and China.

The policy is expected to significantly affect Indian pharmaceutical companies, which supply a large share of generic medicines to the US market. Major players like Sun Pharmaceutical Industries, Dr. Reddy's Laboratories, Cipla, Lupin, and

Aurobindo Pharma could face margin pressure and potential loss of market share as tariffs kick in after the grace period.

Indian firms have been preparing for such scenarios by expanding manufacturing in the US and diversifying to other markets. However, the high tariff levels could disrupt supply chains and increase costs for American consumers and healthcare systems.

The announcement has sparked concerns in India's pharma sector, which contributes substantially to the country's

exports. Industry bodies are expected to engage with the US administration to seek exemptions or longer transition periods for critical medicines.

This policy reflects the US focus on reshoring pharmaceutical production while balancing short-term supply stability. Indian companies are likely to accelerate their USFDA-compliant facility expansions and explore alternative export destinations to mitigate the long-term impact.

मध्य प्रदेश में भारत के पहले 'टेम्पल बॉन्ड्स': उज्जैन तीर्थ राजस्व से निवेशकों को चुकता किया जाएगा

आस्था और अर्थव्यवस्था का अनोखा मेल, राज्य की वित्तीय स्थिति को नई मजबूती

उज्जैन: मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन और आस्था-आधारित निवेश को नई ऊंचाई दी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) द्वारा जारी किए जा रहे देश के पहले 'टेम्पल बॉन्ड्स' के माध्यम से 200 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। यह राशि उज्जैन और आगर-मालवा के 11 प्रमुख मंदिरों के विकास के लिए कुल 1,100 करोड़ रुपये की परियोजना का हिस्सा है। बाकी 275 करोड़ रुपये अर्बन चैलेंज फंड और 625 करोड़ रुपये बैंक फाइनेंसिंग से आएंगे।

ये बॉन्ड 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी होंगे। निवेशकों को तय ब्याज दर के साथ मूलधन की वापसी मंदिरों में प्राप्त दान, चढ़ावा और तीर्थयात्रा राजस्व से की जाएगी। 31 जुलाई 2026 तक लॉन्च होने वाले इन बॉन्ड्स में आम नागरिक, संस्थाएं और भक्त सीधे निवेश कर सकेंगे। यह मॉडल आस्था को वित्तीय सुरक्षा से जोड़ता है, जहां श्रद्धालु न केवल पुण्य कमाएंगे बल्कि आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे।

इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत धक्का मिलेगा। उज्जैन महाकाल मंदिर पहले ही सालाना 144 करोड़ रुपये से अधिक आय

उत्पन्न कर रहा है। नए विकास कार्यों से सड़कें, पार्किंग, जल निकासी, सुरक्षा और अतिथि सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे सिंहस्थ कुंभ 2028 में लाखों श्रद्धालुओं की आमद बढ़ेगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार फले-फूलेंगे। अनुमान है कि टेम्पल इकोनॉमी से हजारों रोजगार सृजित होंगे और जीडीपी में योगदान बढ़ेगा।

आम लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है। भक्तों को अपने धर्म के प्रति योगदान देते हुए रिटर्न मिलेगा, जो पारंपरिक फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ग्रामीण और शहरी युवाओं को निर्माण, पर्यटन गाइड और सेवा क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी। बेहतर बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन स्तर को ऊपर उठाएगा। हालांकि, निवेशकों को जोखिम का आकलन करना चाहिए, क्योंकि चुकौती दान पर निर्भर है।

यह पहल 'फेथ-बेस्ड इन्वेस्टिंग' की नई कड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सफल रही तो पूरे देश में ऐसे मॉडल अपनाए जा सकते हैं। मध्य

प्रदेश सरकार के इस कदम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को 'स्पिरिचुअल हब' के रूप में स्थापित किया जाएगा।



Start SIP now. And let time do the rest.

“Son, one day you'll appreciate the truly important things in life”

Today's Discipline

Tomorrow's Rewards

“Thanks, Dad.”

Not Sure Where To Begin? [Connect To Know More](#)

Is Your Child's Marriage Fund Ready?

Planning for your child's wedding may require a corpus of around **₹24 lakh.**



A SIMPLE PLAN CAN GET YOU THERE



A **₹7,000** SIP



With a **10%** Annual Step-up



For **10** Years



Can build

~ ₹24 Lakh

corpus for child's wedding



Need less than ₹24 lakh?

The rest can support your next big goal vacation, home, retirement, re-investment, or more.

LET'S PLAN FOR THE BIG DAY.

[Connect to know more](#)

*Mutual fund investments are subject to market risk. Assumed returns @12% p.a. Figures are approximate

wealthy



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

☎ (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

☎ (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com



India Accelerates Energy Security with Phase-II Strategic Oil Reserves

₹14,527 Crore PPP Push to Add 6.5 million Tonnes Storage Capacity

Bengaluru: India is set to significantly bolster its energy security by constructing Phase-II of its Strategic Petroleum Reserves (SPR) at an estimated cost of ₹14,527 crore under the Public-Private Partnership (PPP) model. The expansion will add 6.5 million metric tonnes (MMT) of underground storage capacity, taking the country's total strategic reserves well beyond the current 5.33 MMT.

The Phase-II facilities will come up at Chandikhol in Odisha (4 MMT) and Padur in Karnataka (2.5 MMT). These caverns will provide an additional buffer of roughly 9-10 days of national oil consumption, reducing vulnerability to global supply disruptions and price shocks. The PPP framework allows private developers to build, operate and commercially utilise a portion of the storage while ensuring the government retains priority access during emergencies.

Under the revised policy, up to 30 per cent of capacity can be leased to refiners and traders, while another 20 per cent can be used for commercial crude trading. This hybrid model improves project viability through viability gap funding and long-term lease arrangements.

Stocks Likely to Benefit The development is expected to positively impact several listed companies. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) stands to gain from related construction and land ownership opportunities. Engineers India Limited (EIL) is well-positioned for engineering and project management contracts. Megha Engineering & Infrastructures (MEIL) has already secured the Padur facility. Refiners such as Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum could benefit from commercial leasing of storage space,

improving supply chain flexibility and inventory management.

The initiative aligns with India's broader goal of enhancing energy independence and achieving greater resilience against geopolitical risks. Once completed, the expanded SPR network will provide a critical safety net for the economy, supporting industrial growth and consumer price stability. Analysts view this as a strategic long-term positive for the entire oil and gas value chain.



एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज का IPO खुला: भोपाल की IT कंपनी का मेनबोर्ड कदम

प्राइस बैंड ₹120-127, मार्केट कैप ₹664 करोड़; 23 से 27 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन

भोपाल: मध्य प्रदेश की भोपाल स्थित आईटी कंपनी एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) आज 23 जुलाई 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। कंपनी 27 जुलाई तक शेयर जारी करेगी। प्राइस बैंड ₹120 से ₹127 प्रति शेयर तय किया गया है। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹664 करोड़ बैठता है। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें कंपनी लगभग ₹166.80 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है। ऑफर फॉर सेल का कोई हिस्सा नहीं है। इश्यू का लॉट साइज 110 शेयर है, जिससे न्यूनतम निवेश लगभग ₹13,970 बैठता है। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है। अलॉटमेंट 28 जुलाई को होने की संभावना है, जबकि लिस्टिंग 30 जुलाई 2026 को एनएसई और बीएसई पर अपेक्षित है।

एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज 2002 में स्थापित एक इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी एंटरप्राइज एप्लिकेशंस, डिजिटल सर्विसेज, मैनेज्ड सर्विसेज और प्रोग्राइटरी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसके प्रमुख उत्पादों में सिनेर्जी लो-कोड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एक्सट्राट्रस्ट डिजिटल सिग्नेचर सॉल्यूशंस, एसएपी-ओरेकल-आईएफएस ईआरपी प्रैक्टिस, एचआर-पेयरोल सॉल्यूशंस और क्लाउड इंटीग्रेशन सेवाएं शामिल हैं। कंपनी भारत के अलावा यूएसए, कनाडा और सिंगापुर में भी उपस्थिति रखती है।

कंपनी के प्रमोटर्स श्री शुखबीर सिंह, श्री जे.पी. सिंह और श्रीमती शाइनी शुखबीर हैं। शुखबीर सिंह संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वित्तीय रूप से कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। FY 23 में रेवेन्यू ₹225.56 करोड़ से बढ़कर FY 25 में ₹276.08 करोड़ हो गया। ईबीआईटीडीए मार्जिन भी 6 प्रतिशत से सुधरकर लगभग 17 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो ऑपरेशनल दक्षता में सुधार दर्शाता है। आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, सिस्टम और हार्डवेयर खरीदने, वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने तथा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा।

यह आईपीओ मध्य प्रदेश की आईटी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। भोपाल स्थित यह कंपनी अब मेनबोर्ड पर लिस्ट होकर अपनी पहुंच और विस्तार बढ़ाने की तैयारी में है।

एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। कंपनी के पास मजबूत प्रोग्राइटरी प्लेटफॉर्म और लंबे समय का अनुभव है। हालांकि आईटी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी अधिक है। निवेशकों को कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़कर जोखिमों, ग्रोथ प्लान और वैल्यूएशन का आकलन करके ही निवेश का फैसला लेना चाहिए।

यह इश्यू मध्य प्रदेश से आने वाली आईटी कंपनी का मेनबोर्ड पर आने का प्रतीक है और क्षेत्रीय टेक कंपनियों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है।



NAN MagneTech Picks Andhra Pradesh for ₹1,250 Crore Rare Earth Magnet Plant

Strategic Investment to Boost Domestic Manufacturing of Critical Magnets for EVs, Defence & Renewables

Amaravati: NAN Magne-Tech has announced a major investment of ₹1,250 crore to set up a high-performance rare earth permanent magnet manufacturing facility in Andhra Pradesh. The greenfield project will come up at Naidupeta Industrial Park in Nellore district and is expected to strengthen India's self-reliance in critical materials.

The plant will have an annual capacity of 1.2 kilo tonnes of sintered neodymium-iron-boron (NdFeB) magnets, which are essential components for electric vehicle motors, wind turbines, industrial machinery, aerospace systems and defence applications. The facility is scheduled for commercial operations by June 2028 and will generate around 400 direct jobs.

NAN Magne-Tech, promoted by Vedanta Group's executive vice-chairman Navin Agarwal through his holding company, aims to capitalise on the government's Production Linked Incentive (PLI) scheme for rare earth permanent magnets. The

Andhra Pradesh government has extended a tailored incentive package including capital subsidy, power and water concessions, and land support under its industrial policy.

This investment marks a significant step towards reducing India's heavy dependence on Chinese imports of rare earth magnets. With global supply chain concerns rising, domestic manufacturing of these strategic materials has become a national priority.

Stocks Likely to Benefit The development is expected to positively impact several listed companies. Vedanta Limited stands to gain indirectly through promoter linkage and group synergies. Electric vehicle makers such as Tata Motors and Mahindra & Mahindra could benefit from improved local availability of magnets. Renewable energy players like Suzlon Energy and defence PSUs including Bharat Electronics Limited (BEL) and Hindustan Aeronautics Limited (HAL) may see supply chain advantages. Companies

involved in rare earth processing and mining, such as IREL (India) Limited, could also benefit from increased downstream demand.

The project positions Andhra Pradesh as an emerging hub for advanced materials manufacturing and aligns with India's broader goals of critical minerals and high-tech industries. Once operational, the plant will contribute to energy transition, defence modernisation and industrial competitiveness.



कॉम्पिटिशन रेगुलेटर ने जिंदल स्टेनलेस के खिलाफ केस खारिज किया

इंडोनेशिया सप्लायर्स के साथ डील पर राहत, स्टेनलेस स्टील सेक्टर को नई उम्मीद

नई दिल्ली: प्रतिस्पर्धा आयोग ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के खिलाफ इंडोनेशियाई सप्लायर्स से संबंधित डील पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। यह फैसला स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

सीसीआई की जांच में पाया गया कि जिंदल स्टेनलेस की इंडोनेशिया से कच्चे माल की खरीद संबंधी व्यवस्थाएं प्रतिस्पर्धा विरोधी नहीं थीं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि ये डील बाजार दरों पर आधारित थीं और किसी प्रकार की अनुचित लाभप्राप्ति नहीं की गई। आयोग ने उपलब्ध सबूतों के अभाव में मामले को बंद करने का फैसला लिया।

जिंदल स्टेनलेस के लिए यह राहत महत्वपूर्ण है। कंपनी भारत की प्रमुख स्टेनलेस स्टील उत्पादक है और इंडोनेशिया से कच्चे माल की आपूर्ति

उसके उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है। इस फैसले से कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रहेगी और लागत नियंत्रण में मदद मिलेगी। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पूरे सेक्टर के लिए सकारात्मक है। इससे अन्य कंपनियों को भी विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों पर भरोसा बढ़ेगा। स्टेनलेस स्टील की मांग बढ़ रही है, खासकर निर्माण, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता सामान क्षेत्र में।

जिंदल स्टेनलेस के प्रबंधन ने इस फैसले का स्वागत किया है। कंपनी भविष्य में भी पारदर्शी व्यवसायिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए विस्तार की योजनाओं पर काम कर रही है। यह घटनाक्रम भारतीय उद्योग जगत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नियम-आधारित शासन को मजबूत करने का उदाहरण है।



India Rolls Out Simplified Export Rules for Small Shipments to Boost MSME Trade

Easier Norms for Goods Worth Up to Rs 10,000 Aim to Empower Small Businesses and Enhance Export Competitiveness

Mumbai: The Indian government is set to introduce simplified export procedures for micro, small and medium enterprises (MSMEs) shipping goods valued up to Rs 10,000. This move is designed to reduce compliance burden, cut paperwork, and encourage greater participation of small businesses in international trade.

Under the proposed norms, MSMEs will benefit from streamlined documentation, faster clearances, and reduced regulatory requirements for low-value shipments. The initiative is expected to make exporting more accessible for small manufacturers, artisans, and startups who often find current procedures cumbersome and costly.

This policy aligns with the government's broader push to promote exports and integrate MSMEs into global value chains. By lowering entry barriers, authorities hope to boost the overall export basket and create more employment opportunities in the sector.

The decision comes amid efforts to diversify export markets and reduce dependence on traditional sectors. Officials believe that easing rules for small consignments will particularly benefit handicrafts, handlooms, agricultural produce, and niche products.

Industry bodies have welcomed the move, stating it will help thousands of small exporters scale up their operations. The simplified framework is likely to be implemented through digital platforms to ensure transparency and efficiency.

This policy reflects India's commitment to fostering an enabling environment for MSMEs, which form the backbone of the country's economy.



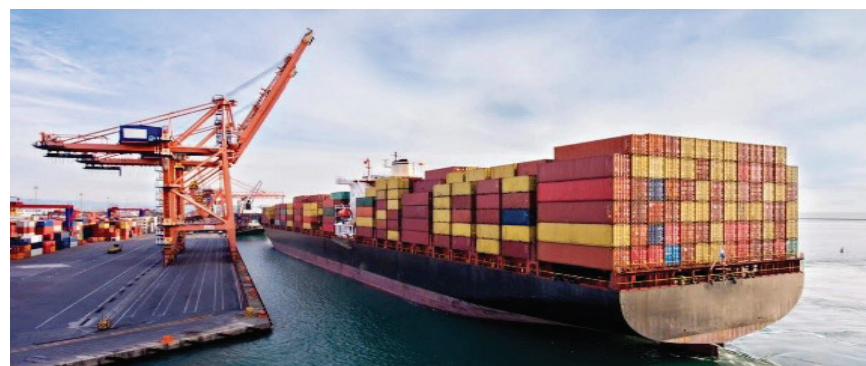
खरीफ सीजन पर संकट के बादल: उर्वरक जहाज बंदरगाहों पर फंसे

पीक बुआई के समय आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंता, किसानों को हो सकती है दिक्कत

नई दिल्ली: देश के प्रमुख बंदरगाहों पर उर्वरक लदे कई जहाज फंसे होने से खरीफ सीजन की चरम बुआई अवधि में आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूरिया, डीएपी और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की खेपें समय पर न पहुंचने से किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध कराने में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

खरीफ सीजन धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दलहन जैसी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में उर्वरक की मांग तेजी से बढ़ती है। बंदरगाहों पर जहाजों के फंसने से अनलॉडिंग में देरी हो रही है, जिससे वितरण श्रृंखला प्रभावित हो रही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और मौसमी व्यवधानों के कारण यह स्थिति और जटिल हो गई है।

सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं। फिर भी मौजूदा देरी से कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर कमी की शिकायतें आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जहाजों की अनलॉडिंग जल्द नहीं हुई तो बुआई प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन पर दबाव पड़ सकता है।



शेयर बाजार पर असर इस विकास से उर्वरक क्षेत्र की कंपनियों पर दबाव देखने को मिल सकता है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ), चंबल फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक फर्टिलाइजर्स और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स (जीएसएफसी) जैसी कंपनियों के शेयरों पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। आपूर्ति में देरी से इन कंपनियों की बिक्री और मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पोर्ट ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर भी अल्पकालिक दबाव दिख सकता है।

सरकार मौजूदा स्टॉक का इस्तेमाल करके आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे उपलब्ध स्टॉक का सही उपयोग करें और अनावश्यक जमाखोरी से बचें।

यह स्थिति कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। समय पर उर्वरक उपलब्धता न केवल किसानों की आय बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ी है। आने वाले दिनों में बंदरगाहों पर अनलॉडिंग की गति और वितरण व्यवस्था सुधारने पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो खरीफ उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है।

AI-Powered Travel Disruptor 30 Sundays Secures \$6.7 Million Funding

Bessemer Venture Partners Leads Round as Platform Redefines Personalized Journeys

मुंबई: AI-based travel platform 30 Sundays has raised \$6.7 million in a fresh funding round led by Bessemer Venture Partners, signalling strong investor confidence in India's growing experiential travel sector. The round also saw participation from existing backers and strategic angels, taking the company's total funding to a notable milestone.

30 Sundays leverages advanced artificial intelligence to curate hyper-personalised travel experiences, moving beyond traditional booking models. The platform analyses user preferences, past trips, and real-time data to recommend tailored

itineraries, hidden gems, and seamless end-to-end planning from flights and stays to unique local experiences.

The fresh capital will fuel product enhancement, AI model refinement, and aggressive expansion across Tier-2 cities. The company aims to strengthen its technology backbone and onboard more partners in hospitality and experiential tourism.

Bessemer Venture Partners, known for backing high-growth tech companies, highlighted 30 Sundays' innovative approach in solving fragmentation in the

travel industry. "Personalisation at scale through AI is the future of travel," a partner noted.

With India's travel and tourism sector rebounding strongly post-pandemic, 30 Sundays is well-positioned to capture a significant share. The platform's focus on authentic, sustainable, and customised journeys aligns perfectly with evolving traveller demands. This funding round underscores the rising interest of global investors in Indian AI startups addressing large domestic markets.

ईवन हेल्थकेयर \$50 मिलियन जुटाने की तैयारी में: खोसला वेंचर्स और अल्फा वेव का बड़ा निवेश हेल्थकेयर स्टार्टअप को मिलेगा मजबूत फंडिंग बूस्ट, डिजिटल हेल्थ सेक्टर में तेजी

नई दिल्ली: भारतीय हेल्थकेयर सेक्टर की उभरती कंपनी ईवन हेल्थकेयर खोसला वेंचर्स और अल्फा वेव ग्लोबल के साथ \$50 मिलियन (लगभग ₹420 करोड़) की फंडिंग राउंड पर चर्चा कर रही है। यह डील सफल होने पर कंपनी की विस्तार योजनाओं को नई गति मिलेगी और डिजिटल हेल्थकेयर सेवाओं को और मजबूती प्रदान करेगी।

ईवन हेल्थकेयर प्राथमिक रूप से टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर समाधान प्रदान करती है। कंपनी ने महामारी के बाद तेजी से विकास किया है और अब Tier-2, Tier-3 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है। नए फंड का उपयोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड, टीम विस्तार और नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए किया जाएगा।

अल्फा वेव ग्लोबल की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा दर्शाती है। इस फंडिंग से ईवन हेल्थकेयर की वैल्यूएशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश की लहर जारी रहेगी। बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, स्मार्टफोन पेन्ट्रेशन और सरकारी डिजिटल हेल्थ पहलों के कारण यह क्षेत्र आकर्षक बना हुआ है। ईवन हेल्थकेयर का यह राउंड अन्य स्टार्टअप्स के लिए भी सकारात्मक संकेत है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यह फंडिंग कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सफलता पर यह डील भारतीय हेल्थकेयर

इकोसिस्टम को वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत करेगी।



Bistro Remains Resilient Amid Rising Competition in Quick Delivery Space

Deepinder Goyal Highlights Limited Impact from Swiggy's Toing & Rapido's Ownly

Mumbai: Zomato's ultra-fast delivery experiment Bistro continues to show resilience despite aggressive moves by competitors in the budget and quick commerce food delivery segment. Speaking on the evolving market dynamics, Zomato CEO Deepinder Goyal noted that Bistro has experienced only limited impact from Swiggy's Toing and Rapido's Ownly initiatives.

Goyal emphasised that Bistro's focused approach on curated snacking and convenience is carving out a distinct niche. While Toing and Ownly target price-sensitive consumers with low or zero commissions and

aggressive marketing, Bistro maintains a differentiated model that complements rather than directly competes with the core Zomato platform.

Industry observers point out that the quick delivery space is witnessing intense experimentation. Swiggy's Toing has expanded rapidly, gaining traction through heavy performance marketing, while Rapido's Ownly focuses on hyperlocal density. However, analysts caution about sustainability, as high subsidies may not translate into long-term profitable growth or incremental demand.

Zomato remains committed to refining Bistro as a small but promising experiment. The company believes such

innovations will ultimately benefit the broader ecosystem by bringing new users into organised food delivery.

This development underscores the maturing Indian food delivery market, where players are balancing growth with profitability.



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23767	24812	24539	24153	23880	23494	23221	22835
BANK NIFTY	56694	60124	59177	57935	56988	55746	54799	53557
SENSEX	76060	80320	79235	77648	76563	74976	73891	72304
FINNIFTY	25910	27413	27018	26464	26069	25515	25120	24566
MIDCAP	14436	15369	15101	14769	14501	14169	13901	13569
ACC	1345	1470	1433	1389	1352	1308	1271	1227
AXISBANK	1230	1344	1314	1272	1242	1200	1170	1128
ABCAPITAL	394	434	423	408	397	382	371	356
BHARTIARTL	1900	2023	1989	1945	1911	1867	1833	1789
BHEL	417	454	440	429	415	404	390	379
BIOCON	435	460	452	443	435	426	418	409
BEL	405	420	416	410	406	400	396	390
CDSL	1335	1507	1461	1398	1352	1289	1243	1180
DATAPATTERN	4580	5908	5370	4975	4437	4042	3504	3109
ESCORTS	2910	3162	3099	3005	2942	2848	2785	2691
EICHERMOTOR	7648	8110	7949	7799	7638	7488	7327	7177
FEDERAL BANK	355	376	366	361	351	346	336	331
GRINFRAPROJECT	878	989	959	919	889	849	819	779
HDFCBANK	744	830	810	777	757	724	704	671
HCLTECH	1269	1373	1324	1297	1248	1221	1172	1145
HINDUNILVR	2146	2205	2185	2166	2146	2127	2107	2088
HAL	4578	4816	4721	4650	4555	4484	4389	4318
HYUNDAI	1953	2065	2032	1993	1960	1921	1888	1849
IOC	139	150	147	143	140	136	133	129
ICICIBANK	1436	1532	1506	1471	1445	1410	1384	1349
INFY	1040	1181	1143	1091	1053	1001	963	911
ITC	284	292	289	286	283	280	277	274
KOTAKBNK	384	405	397	391	383	377	369	363
LICHOUSING	540	577	565	553	541	529	517	505
LT	3790	3999	3929	3860	3790	3721	3651	3582
LUPIN	2371	2666	2595	2483	2412	2300	2229	2117
MARUTI	13450	14420	14126	13788	13494	13156	12862	12524
M&M	3165	3347	3298	3232	3183	3117	3068	3002
MGL	1079	1137	1120	1099	1082	1061	1044	1023
MAZGAONDOC	2302	2437	2399	2350	2312	2263	2225	2176
PFC	412	437	427	420	410	403	393	386
RECLTD	361	380	372	367	359	354	346	341
RELIANCE	1281	1413	1379	1330	1296	1247	1213	1164
SBIN	1012	1118	1093	1052	1027	986	961	920
SUNPHARMA	1937	2003	1985	1961	1943	1919	1901	1877
SHRIRAMFINANCE	1006	1145	1112	1059	1026	973	940	887
TITAN	4690	4875	4804	4747	4676	4619	4548	4491
TCS	2252	2381	2332	2292	2243	2203	2154	2114
TATAMOTORS	324	355	347	335	327	315	307	295
UPL	603	645	634	618	607	591	580	564
VALIENT	264	290	283	274	267	258	251	242
WIPRO	177	184	181	179	176	174	171	169

खरीफ बुवाई में 6% की गिरावट: मानसून की देरी और अनियमित बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी

कृषि उत्पादन पर असर, सरकार की नजर; फर्टिलाइजर और एग्री कंपनियों के शेयरों में दबाव

नई दिल्ली: चालू खरीफ मौसम में बुवाई में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। मानसून की देरी और अनियमित बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और दालों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है।

मानसून की धीमी प्रगति और कुछ राज्यों में सूखे जैसे हालात ने खरीफ फसलों की बुवाई को प्रभावित किया है। किसान अनियमित बारिश के कारण फसल चक्र बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं। सरकार ने स्थिति पर नजर रखते हुए सिंचाई सुविधाओं और बीज वितरण को तेज करने के निर्देश दिए हैं।

इस खबर से फर्टिलाइजर कंपनियों जैसे Chambal Fertilisers, Coromandel International, National Fertilizers और RCF के शेयरों पर दबाव पड़ सकता है। एग्री इनपुट और ट्रैक्टर कंपनियां जैसे Escorts Kubota, Mahindra & Mahindra भी प्रभावित हो सकती हैं।

यह स्थिति खाद्य सुरक्षा और किसान आय दोनों के लिए चुनौती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है।



Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.